NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Delhi, 08/05/2026

Page No: 14, Size: 17.97cm × 14.16cm

नर्सिंग कॉलेज में 19 छात्राएं टीबी से ग्रसित, रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शिमला नर्सिंग कॉलेज में 19 छात्राओं को टीबी की बीमारी मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परिसर के हाल ही में हुए दो निरीक्षणों के दौरान छात्रावास के प्रबंधन में कई गंभीर कमियां पाई गईं। इनमें साफ-सफाई और संस्थान के समग्र कामकाज से जुड़ी कमियां शामिल थीं। हालांकि, अफसरों द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए और इसके परिणामस्वरूप छात्रों को टीबी हो गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Delhi, 08/05/2026

Page No: 2, Size: 13.18cm × 8.68cm

दो सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में निगम व पुलिस आयुक्त को नोटिस

भास्कर न्यूज|फरीदाबाद

ग्रेटर फरीदाबाद में पुरी प्राणायाम सोसायटी के सामने सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मांगी गई रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी शामिल करने को कहा है। बता दें दो मई को पुरी प्राणायाम सोसाइटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों खेड़ी गांव निवासी सुनील और राजेंद्र की दम घुटने से मौत हो गई थी। दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण व गैस मास्क के सीवर में उतारा गया था। आरोप है दोनों बीपीटीपी कंपनी के कर्मचारी थे। एस्टेट मैनेजर के कहने पर दोनों सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे। इस मामले में बीपीटीपी थाने की पुलिस ने बीपीटीपी कंपनी के संबंधित प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मामले में आयोग की टिप्पणी

एनएचआरसी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एनएचआरसी की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश पहले से मौजूद हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran (Jagran City), Faridabad, 08/05/2026

Page No: 2, Size: 20.29cm × 29.90cm

सीवर सफाई के दौरान दो कर्मियों की मौत पर एनएचआरसी सख्त, सीपी व निगमायुक्त को नोटिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्रणायाम सोसायटी के सामने सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मांगी गई रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति और मृतकों के स्वजन को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी शामिल करने को कहा है।

दो मई को पुरी प्रणायाम सोसायटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों गांव खेड़ी के निवासी सुनील और राजेंद्र की दम घुटने से मौत हो गई थी। दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क के सीवर में उतारा गया था। आरोप है कि दोनों बीपीटीपी के कर्मचारी थे और एस्टेट मैनेजर के कहने पर दोनों सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे। एनएचआरसी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है।

आयोग ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एनएचआरसी की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सीवर सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल और सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Faridabad, 08/05/2026

Page No: 1, Size: 12.62cm × 15.50cm

सीवर की सफाई के दौरान मौत के मामले में नोटिस

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया
- सीपी-निगमायुक्त को दो हफ्ते में जवाब देना होगा

फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी के पास सीवर की सफाई के दौरान मारे गए दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त और नगरनिगम आयुक्त को नोटिस भेजा है।

आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इसमामले में हुई लापरवाही की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को दिए मुआवजे की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन करार दिया है। आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और आयोग की एडवाइजरी के बावजूद सीवर की सफाई सफाई कर्मियों से करवाई जा रही है। जबकि सीवर की सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल करने और सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के नियम-कायदे पहले से ही तय हैं।

बता दें कि दो मई को ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्रथम सोसाइटी के पास सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में घुसे दो सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान खेड़ी कलां गांव निवासी सुपरवाइजर सुनील और राजेंद्र के रूप में हुई थी।

सीवर में दो मजदूरों की मौत पर मानवाधिकार आयोग का नोटिस

NBT रिपोर्ट, फरीदाबाद : ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्राणायाम सोसायटी में सीवर सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए निगम और पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

तीन दिन पहले सोसायटी के बाहर सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। बताया गया कि दोनों मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतारा गया था। उनके पास न तो ऑक्सीजन सिलेंडर था और न ही गैस मास्क उपलब्ध कराया गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। लोगों का आरोप था कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण दो लोगों की जान चली गई। अब आयोग ने प्रशासन से पूछा है कि घटना की जांच किस स्तर तक पहुंची, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। साथ ही मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है।

थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

अधिकारी देंगे जवाब

- आयोग ने कहा कि सीवर सफाई में मशीनों का उपयोग और कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है

Daily Hunt, Online News, 08/05/2026

Source: https://m.dailyhunt.in/news/india/english/hindusthan+samachar+english-epaper-hinsamen/nhrc+takes+suo+motu+cognizance+of+young+female+inmates+death+in+deoghar+remand+home-newsid-n711393976

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Young Female Inmate's Death in Deoghar Remand Home
Hindusthan Samachar 12 hrs ago

New Delhi, 07 May (H.S.):

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the suspicious death of a young female inmate at a remand home in Deoghar district, Jharkhand.
The Commission issued notices to the state's Chief Secretary and Deoghar Superintendent of Police (SP), seeking a detailed report within two weeks.

NHRC stated that according to media reports, on May 2, the condition of a 19-year-old female inmate at a remand home in Deoghar's Charkhi Pahari area suddenly deteriorated. Remand home staff rushed her to Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment. The cause of death remains undetermined.

Reports indicate five inmates have died at this remand home since January 1, 2026, raising serious questions about its safety and management.

Hindusthan Samachar / Jun Sarkar

Source: https://zeenews.india.com/india/19-year-old-girl-dies-mysteriously-in-jharkhand-remand-home-nhrc-seeks-report-from-govt-3045534.html

NewsIndia19-Year-Old girl dies mysteriously in Jharkhand remand home; NHRC seeks report from Govt
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF INDIA (NHRC)
19-Year-Old girl dies mysteriously in Jharkhand remand home; NHRC seeks report from Govt
The NHRC took suo motu cognisance of a media report regarding the death of the 19-year-old female inmate on May 2 under allegedly suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.

|Last Updated: May 07, 2026, 09:56 PM IST|Source: IANS

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report within two weeks from the Jharkhand government and the district police chief over the death of a 19-year-old woman inmate at a remand home in the Charki Pahadi area of Deoghar district earlier this month, an official said.
The NHRC took suo motu cognisance of a media report regarding the death of the 19-year-old female inmate on May 2 under allegedly suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.
The Commission observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of human rights violations.
Accordingly, it issued notices to the Chief Secretary of the Government of Jharkhand and the Superintendent of Police, Deoghar, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report published on May 4, when the inmate's condition suddenly deteriorated, the remand home staff rushed her to Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment.

Reportedly, five inmates of the remand home have died since January 1, 2026, raising serious questions about the institution's security and healthcare arrangements, the statement said.

In a separate case, the Commission also took suo motu cognisance of a media report stating that two sanitation workers died while cleaning a sewer at the Puri Pranayam Society in Greater Faridabad, Haryana, on May 2.

According to the report, the workers entered a manhole on the directions of the estate manager of the building without being provided protective gear or gas masks.

The Commission observed that the contents of the report, if true, indicate a serious violation of human rights.

The NHRC has therefore issued notices to the Commissioner of the Municipal Corporation and the Commissioner of Police, Faridabad, Haryana, seeking a detailed report within two weeks. The report is expected to include the status of the investigation and details of compensation paid to the next of kin of the deceased workers.

While issuing the notices, the Commission expressed concern that despite guidelines issued by the Supreme Court and NHRC advisories emphasising mechanised sewer cleaning and adequate safety gear for sanitation workers, such incidents continue to occur frequently across the country.

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

Punjab Kesari, Online News, 08/05/2026

Source: https://english.punjabkesari.com/india/jharkhand-remand-home-death-nhrc-seeks-govt-police-report-within-two-weeks/

India
Jharkhand remand home death: NHRC seeks report from govt within two weeks
By: IANS
On: Thursday, May 7, 2026 9:22 PM

New Delhi, May 7 (IANS) The NHRC has sought a report within two weeks from the Jharkhand government and the district police chief over the death of a 19-year-old woman inmate of a remand home in the Charki Pahadi area of the Deoghar district earlier this month, an official said.

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report about the death of a 19-year-old female inmate on May 2, allegedly under suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.

The NHRC observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

It issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand, and the Superintendent of Police, Deogarh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on May 4, when the inmate's condition suddenly deteriorated, the Remand Home staff rushed her to the Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment.

Reportedly, five inmates of this Remand Home have died since January 1 2026, raising questions about its security and arrangements, said a statement.

In a separate case, the Commission took suo motu cognisance of a media report that two sanitation workers died while cleaning a sewer at the Puri Pranayam Society in Greater Faridabad, Haryana, on May 2.

The report said that the workers had entered a manhole on the directions of the Estate Manager of the building without being provided any protective gear or gas masks.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

Therefore, it has issued notices to the Commissioner, Municipal Corporation, and the Commissioner of Police, Faridabad, Haryana, calling for a detailed report in the matter within two weeks. It is expected to include the status of the investigation and compensation paid to the next of kin of the deceased persons.

Issuing the notices, the Commission has noted with concern that despite guidelines issued by the Supreme Court and the NHRC advisory emphasising the use of mechanised cleaning of sewers with adequate safety gear to the sanitation workers, such incidents continue to occur frequently in the country.

–IANS

Source: https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-questions-himachal-govt-over-19-women-nursing-students-contracting-tb

NHRC questions Himachal govt over 19 women nursing students ‘contracting TB’
NHRC Intervenes After Reports of Tuberculosis Outbreak and Inmate Death in Institutional Facilities
The Hawk
May 07, 2026, 08:28 PM

New Delhi, May 7 (IANS) Taking a strong view, the NHRC has sought a report from Himachal Pradesh after a media report alleged that 19 women students contracted tuberculosis in the hostel of a Nursing College in Shimla, an official said.

Taking suo motu cognisance of a media report over the alleged incident, the National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Chief Secretary, Himachal Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Reportedly, during two recent inspections of the premises, serious deficiencies were observed in the management of the hostel, including sanitation and overall institutional functioning. However, no corrective measures were taken by the authorities, and as a result, the students contracted tuberculosis.

The Commission observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

The media report, carried on May 2, highlighted several shortcomings based on the two inspections of the institutions held on March 31 and April 17.
The students at the hostel face overcrowded, damp, and unhygienic living conditions with severely inadequate sanitation. Food quality is poor and lacks basic nutrition. They are reportedly denied rest during illness and forced to work as "hospital staff" even on holidays, an NHRC statement said.
In a separate case, the NHRC sought a report within two weeks from the Jharkhand government and the district police chief over the death of a 19-year-old woman inmate of a remand home in the Charki Pahadi area of the Deoghar district earlier this month, an official said.

The NHRC took suo motu cognisance of a media report about the death of a 19-year-old female inmate on May 2, allegedly under suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.

The NHRC observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

It issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand, and the Superintendent of Police, Deogarh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on May 4, when the inmate’s condition suddenly deteriorated, the Remand Home staff rushed her to the Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment.

Reportedly, five inmates of this Remand Home have died since January 1 2026, raising questions about its security and arrangements, said a statement.

--IANS

Source: https://news.careers360.com/nhrc-nursing-college-himachal-pradesh-shimla-mgmsc-tuberculosis-tb-outbreak-19-female-poor-food-unhygienic-hostel-report-2-week

Home > Colleges On Campus News > NHRC takes suo motu cognizance of TB outbreak at MGMSC Nursing College hostel affecting 19 female students

NHRC takes suo motu cognizance of TB outbreak at MGMSC Nursing College hostel affecting 19 female students
Vaishnavi Shukla |
May 7, 2026 |
06:36 PM IST | 2 mins read
MGMSC Nursing College Shimla: NHRC seeks a detailed report from the state's chief security officer within two weeks, flagging the incidents as a violation of human rights

Shimla Nursing College: The National Human Rights Commission (NHRC) India has taken suo motu cognizance after several media reports highlighted that 19 female students were contracted tuberculosis due to unhygienic living conditions in Shimla's MGMSC Nursing College hostel.
NHRC India has issued a notice to Himachal Pradesh's chief security and called for a detailed report on the incidents happening at the Shimla nursing college, within two weeks.
According to the official PIB press release, the students at the MGMSC Nursing College hostel are reportedly facing severely overcrowded, damp, and unhygienic living conditions with inadequate sanitation.
The commission has further noted that it's a serious issue of "human rights violation" if the media reports circulating are true.

Source: https://en.themooknayak.com/india/nhrc-closes-enquiry-against-journalist-omar-rashid-as-victim-refuses-to-reveal-identity

India
NHRC Closes Enquiry Against Journalist Omar Rashid as Victim Refuses to Reveal Identity

In its report submitted on October 6, 2025, the Delhi Police informed the NHRC that the complainant (the alleged victim) had refused to share her identity and address, and showed no interest in proceeding with the case. Consequently, the police concluded that no further action was warranted.
The Commission had initially taken up the matter following anonymous social media allegations of serious offences, including rape and "force-feeding beef," levelled against Rashid.
Geetha Sunil Pillai
Published on:
07 May 2026, 6:35 pm

New Delhi- The National Human Rights Commission (NHRC) has closed its case against journalist Omar Rashid, citing the Delhi Police report that found no grounds for further action after the alleged victim declined to disclose her identity or pursue the matter.

The NHRC, in its final order, stated that no further intervention was required. The Commission had initially taken up the matter following anonymous social media allegations of serious offences, including rape and "force-feeding beef," levelled against Rashid.

The case originated in May 2025 when Tanmay N., convenor of the Sahyadri Rights Forum, approached the NHRC seeking an investigation based on the unverified social media posts. On May 23, 2025, an NHRC bench headed by Priyank Kanoongo registered the case, naming both Omar Rashid and the news portal The Wire (where he was then employed), and directed the Delhi Police Commissioner to probe the allegations.

In its report submitted on October 6, 2025, the Delhi Police informed the NHRC that the complainant (the alleged victim) had refused to share her identity and address, and showed no interest in proceeding with the case. Consequently, the police concluded that no further action was warranted.

Omar Rashid subsequently moved the Delhi High Court for a speedy resolution of the NHRC proceedings. On November 7, 2025, the High Court directed the Commission to dispose of the matter within six weeks.

The NHRC took up the case again on January 21, 2026, providing the complainant Tanmay N. an opportunity to respond to the Delhi Police report and sharing a copy with Rashid as well. However, by its proceedings on March 13, the Commission noted that no response had been received from the complainant.

“In view of the above facts and circumstances, the Commission is of the opinion that no further intervention is warranted in the matter. The case is closed,” the NHRC said in its order.

The closure comes after an inquiry process that lasted over 300 days.
In a detailed social media post on May 7, journalist Omar Rashid broke his silence on the year-long ordeal

following the National Human Rights Commission's closure of the case against him. He described the May 2025 anonymous social media campaign as a "fake, malicious, and communally provocative" hate operation orchestrated through fabricated allegations of rape and "force-feeding beef," designed to inflame communal tensions by invoking tropes of love jihad, beef, and Kashmir.

Rashid claimed that the entire narrative was fictional, including a non-existent "young Hindu woman" victim, and revealed that the Delhi Police Action Taken Report identified the source as a 34-year-old practicing advocate and political activist who refused to cooperate, threatened the investigating officer, denied filing any complaint, and evaded verification.

He recounted the severe personal trauma inflicted on him and his family, including death threats, communal abuse, attempts to desecrate his late mother's memory, and financial harassment, while emphasizing his consistent cooperation with The Wire's internal probe, the Delhi Police, and the NHRC proceedings. Rashid expressed gratitude to the Delhi Police for providing security and stated that he now intends to pursue legal accountability against the perpetrators, who he said misused their position as advocates to weaponize disinformation and obstruct justice.

The Mooknayak reached out to NHRC member Priyank Kanungo, who led the bench that took cognizance of the case, to seek more details and comments on the closure. However, his phone remained unavailable. The report will be updated if and when he responds.

The Mooknayak also contacted Tanmay N., convenor of the Sahyadri Rights Forum, to understand his reasons for approaching the NHRC and his views on the police report and the final closure of the case. The response from him is awaited.

NDTV, Online News, 08/05/2026

Source: https://ndtv.in/india/tuberculosis-spreads-in-shimla-nursing-hostel-19-students-suffer-from-tb-nhrc-seeks-response-from-government-11463154

शिमला के नर्सिंग हॉस्टल में फैली बीमारी, 19 छात्राएं टीबी ग्रसित, NHRC ने सरकार से मांगा जवाबआयोग के मुताबिक हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अत्यधिक भीड़भाड़, सीलन और बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रही हैं. हॉस्टल में स्वच्छता की व्यवस्था अपर्याप्त है. साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी खराब है और उसमें बुनियादी पोषण की कमी है.
Reported by:
हिमांशु शेखर मिश्रा पल्लव मिश्रा Edited by: आलोक कुमार ठाकुर देश मई 07, 2026 20:10 pm IST

शिमला के MGMSC नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में उन्नीस छात्राओं के तपेदिक (Tuberculosis) से संक्रमित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले से जुडी मीडिया ख़बरों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा गुरुवार को जारी एक नोट के मुताबिक परिसर में हाल में किए गए दो निरीक्षणों में हॉस्टल में स्वच्छता और व्यवस्था संबंधी कई गंभीर कमियां पाई गई हैं. अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय न किए जाने से छात्राएं तपेदिक से संक्रमित हो गईं. मीडिया रिपोर्ट सही होने पर यह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है.

NHRC ने नोटिस जारी करने के दौरान 2 मई 2026 को छपे एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 31 मार्च और 17 अप्रैल 2026 को संस्थान में दो बार हुए निरीक्षणों में कई कमियां उजागर हुईं थी लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की.

आयोग के मुताबिक हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अत्यधिक भीड़भाड़, सीलन और बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रही हैं. हॉस्टल में स्वच्छता की व्यवस्था अपर्याप्त है. साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी खराब है और उसमें बुनियादी पोषण की कमी है. कहा गया है कि बीमारी के दौरान भी उन्हें आराम नहीं दिया जाता और छुट्टियों में भी उन्हें अस्पताल कर्मचारी के रूप में काम करने को मजबूर किया जाता है.
गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने झारखंड के देवघर में एक रिमांड होम में 2 मई, 2026 को एक 19 वर्षीय युवती की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और देवघर पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगा है.

NHRC ने अपने आदेश में कहा "उसकी (युवती) मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य, यदि सत्य हैं तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाते हैं...4 मई 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई तो रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. खबरों के अनुसार, पहली जनवरी 2026 से अब तक इस रिमांड होम में पांच कैदियों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं".

Magzter, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.magzter.com/stories/newspaper/The-Daily-Guardian/NHRC-SEEKS-HEALTH-MINISTRY-REPORT-ON-RG-KAR-CASE

NHRC seeks Health Ministry report on RG Kar case
The Daily Guardian May 07, 2026

In a major development following the West Bengal election results, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken a strong and unprecedented stand in the RG Kar Medical College case, significantly escalating pressure on the Ministry of Health & Family Welfare.

- TDG NETWORK
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Acting on a complaint filed by Dr. Lakshya Mittal, Chairperson of the United Doctors' Front (UDF), the NHRC has directed the Secretary of the Ministry of Health & Family Welfare to submit a detailed compliance report within four weeks. Failing this, the Commission has warned of invoking its powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, which includes summoning the concerned authority for a personal appearance. This strict directive comes after repeated noncompliance despite earlier orders, reflecting the Commission's serious concern over continued inaction in the RG Kar case.

UDF emphasised that this decisive action has come immediately after the West Bengal election results, marking a turning point in accountability. For the first time, with the same political leadership at the Centre and now in West Bengal, there exists a clear opportunity to implement long-pending healthcare reforms without administrative or political barriers.

"There are no excuses left now. The system must deliver," said Dr. Lakshya Mittal. Recalling the tragic incident of August 2024, where a young postgraduate doctor lost her life after being subjected to extreme working conditions, UDF reiterated that this is not just a case but a symbol of systemic failure. Dr. Mittal stated that Dr. Abhaya is not just a victim, but Bengal's daughter, and justice for her must now translate into structural reform across India.

The Commission has specifically sought compliance with earlier directions dated June 11, 2025, action taken against officials responsible at RG Kar Medical College, and the enforcement of duty-hour regulations under existing norms. Failure to respond may lead to the personal appearance of senior authorities before the NHRC, signalling serious legal consequences for continued negligence. UDF reiterated that resident doctors across India are routinely subjected to 80-100-hour workweeks in violation of prescribed norms, noting that the NHRC has rightly recognised this institutionalised exploitation as a human rights issue that requires immediate enforcement. The UDF's key demands include the immediate nationwide enforcement of the Uniform Residency Scheme of 1992, NMC-led surprise audits of duty hours across all institutions, strict action against institutions and officials violating norms, and the creation of transparent and accountable monitoring systems.

Dainik Bhaskar, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/haryana/faridabad/ballabgarh/news/faridabad-sewer-deaths-human-rights-commission-issues-notice-137879204.html

फरीदाबाद नगर निगम-पुलिस आयुक्त को मानवाधिकार आयोग का नोटिस:सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
बल्लभगढ़, फरीदाबाद13 घंटे पहले

ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्रणायाम सोसाइटी के सामने सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की पूरी जानकारी शामिल की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की घटनाएं सफाई कर्मियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं।

पांच दिन पहले हुई थी दो कर्मचारियों की मौत

दरअसल, 2 मई को ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्रणायाम सोसाइटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान गांव खेड़ी निवासी सुनील और राजेंद्र के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क के सीवर में उतारा गया था। सीवर के अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण दोनों की हालत बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों कर्मचारी बीपीटीपी से जुड़े हुए थे और एस्टेट मैनेजर के कहने पर उन्हें मैनहोल में सफाई के लिए उतारा गया था। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था।
आयोग ने कहा - मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन

मानवाधिकार आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह मामला मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रतीत होता है। आयोग ने यह भी चिंता जताई कि भारत का सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देशों और आयोग की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।

आयोग ने कहा कि सीवर सफाई के लिए मशीनों के उपयोग और सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद कई स्थानों पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे सफाई कर्मियों की जान जोखिम में पड़ रही है। वहीं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Source: https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/nhrc-closes-case-against-journalist-omar-rashid-as-delhi-police-concludes-no-action-needed-on-anonymous-rape-allegations-533185

Home / मुख्य सुर्खियां / NHRC ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ.....
NHRC ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ बंद किया रेप केस, कार्रवाई के लिए नहीं मिला कोई आधार
Shahadat
7 May 2026 10:06 AM (2 mins read)

300 दिनों से ज़्यादा चली जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ अपना केस बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस को पिछले साल सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगाए गए गुमनाम आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं मिला। यह केस मई 2025 में NHRC की एक बेंच ने शुरू किया था, जिसकी अगुवाई प्रियंका कानूनगो कर रहे थे। यह केस सोशल मीडिया पर की गई कुछ गुमनाम पोस्ट पर आधारित था, जिनमें राशिद पर गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए, जिनमें कथित रेप और "ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाना" शामिल था। हालांकि, पुलिस जांच में यह नतीजा निकला कि इस मामले में किसी भी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है।

इस बीच उमर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और NHRC के सामने चल रहे केस का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की। 7 नवंबर, 2025 को हाईकोर्ट ने राशिद की याचिका का निपटारा करते हुए NHRC से कहा कि वह इस मामले का निपटारा छह हफ़्तों के अंदर करे। इसके बाद आयोग ने 21 जनवरी, 2026 को इस मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता (तन्मय एन.) को दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर अपना जवाब देने का मौका दिया गया। रिपोर्ट की एक कॉपी उमर राशिद को भी दी गई।

हालांकि, 13 मार्च, 2026 को हुई अपनी कार्यवाही में NHRC ने कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के संबंध में शिकायतकर्ता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। NHRC ने यह नतीजा निकाला कि इस मामले में अब आगे किसी भी दखल की ज़रूरत नहीं है। NHRC ने अपने अंतिम आदेश में कहा, "उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आयोग की राय है कि इस मामले में अब और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह मामला बंद किया जाता है।"

Hindustan, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.livehindustan.com/ncr/faridabad/story-national-human-rights-commission-takes-notice-on-deaths-of-two-safai-karamcharis-in-faridabad-201778167638212.amp.html

सफाई कर्मियों की मौत के मामले में प्रशासन को नोटिस
May 07, 2026 08:57 pm IST
Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी के पास सीवर की सफाई के दौरान मारे गए दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त और नगरनिगम आयुक्त को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।
मामले की लापरवाही
आयोग ने दोनों अधिकारियों से इसमामले में हुई लापरवाही की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस मामले में हुई कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन करार दिया है। आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और आयोग की एडवाइजरी के बावजूद सीवर की सफाई सफाई कर्मियों से करवाई जा रही है। जबकि सीवर की सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल करने और सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के नियम-कायदे पहले से ही तय हैं।

मृतकों की पहचान
बता दें कि दो मई को ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्रथम सोसाइटी के पास सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में घुसे दो सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान खेड़ी कलां गांव निवासी सुपरवाइजर सुनील और राजेंद्र के रूप में हुई थी। जांच में दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क के सीवर में उतारने का आरोपहै। इस मामले में बीपीटीपी थाना पुलिस ने मृतकों में से एक सुनील के भाई लाला की शिकायत पर बीपीटीपी केसंपदा प्रबंधक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था।
अंतिम टिप्पणी

सामान्य प्रश्न
✦
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस मामले में नोटिस भेजा है?
आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर सफाई के दौरान मरे दो सफाई कर्मियों के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को नोटिस भेजा है।
✦
मृतक सफाई कर्मियों की पहचान क्या है?

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Online News, 08/05/2026

Source: https://uditvani.in/new-delhi/nhrc-notice-jharkhand-government-deoghar-remand-home-inmate-death/

शिमला नर्सिंग कॉलेज में 19 छात्राओं को टीबी, एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट
7 May 2026 10:20 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शिमला नर्सिंग कॉलेज में 19 छात्राओं को टीबी मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शिमला नर्सिंग कॉलेज में 19 छात्राओं को टीबी मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट एक मीडिया रिपोर्ट के बाद मांगी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिमला के एक नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में 19 महिला छात्रों को टीबी (तपेदिक) हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी। इस कथित घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आयोग ने दो हफ्तों के भीतर इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक, परिसर के हाल ही में हुए दो निरीक्षणों के दौरान, हॉस्टल के प्रबंधन में कई गंभीर कमियां पाई गईं। इनमें साफ-सफाई और संस्थान के समग्र कामकाज से जुड़ी कमियां शामिल थीं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, और इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को टीबी हो गया। आयोग ने टिप्पणी की कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। 2 मई को प्रकाशित हुई मीडिया रिपोर्ट में 31 मार्च और 17 अप्रैल को संस्थान में हुए दो निरीक्षणों के आधार पर कई कमियों को उजागर किया गया था। एनएचआरसी के एक बयान के मुताबिक, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भीड़भाड़ वाली, सीलन भरी और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, जहां साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद अपर्याप्त है। भोजन की गुणवत्ता भी खराब है और उसमें बुनियादी पोषण तत्वों की कमी है। कथित तौर पर बीमार होने पर भी छात्रों को आराम करने की अनुमति नहीं दी जाती और छुट्टियों के दिनों में भी उन्हें 'अस्पताल के कर्मचारियों' के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अन्य मामले में एक अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी ने झारखंड सरकार और जिला पुलिस प्रमुख से दो हफ्तों के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट देवघर जिले के चरकी पहाड़ी इलाके में स्थित एक रिमांड होम में रह रही 19 वर्षीय महिला कैदी की इस महीने की शुरुआत में हुई मौत के संबंध में मांगी गई है। एनएचआरसी ने 2 मई को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत का जिक्र था। आरोप है कि यह मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उसकी मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आयोग ने टिप्पणी की कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर दो हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 4 मई को आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई तो रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर 1 जनवरी 2026 से इस रिमांड होम के पांच कैदियों की मौत हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।

Vocal TV, Online News, 08/05/2026

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-jharkhand-govtphp/cid18630150.htm

Home राष्ट्रीय
देवघर की एक युवती कैदी की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
By VocalTV Desk | May 7, 2026, 18:29 IST

नई दिल्ली, 07 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड के देवघर जिले में एक रिमांड होम की युवती कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और देवगढ़ पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने बताया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 2 मई को देवघर जिले के चरखी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक रिमांड होम की युवती (19) कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई। उसी दौरान रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

खबरों के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से इस रिमांड होम में पांच कैदियों की मौत हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/11369/nhrc-issued-notice-to-jharkhand-cs-seeking-report-on-the-death-of-a-deoghar-based-remand-homes-female-inmate

HomeTop StoriesNHRC issued notice to Jharkhand CS, seeking report on the death of a Deoghar based Remand Home's female inmate

NHRC issued notice to Jharkhand CS, seeking report on the death of a Deoghar based Remand Home's female inmate

Administrator 08 May 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report about the death of a 19-year-old female inmate of a Remand Home in the Charki Pahadi area of the Deoghar district of Jharkhand on 02nd May 2026 under suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand and the Superintendent of Police, Deogarh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 04th May 2026, when the inmate's condition suddenly deteriorated, the Remand Home staff rushed her to the Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment. Reportedly, five inmates of this Remand Home have died since 1st January 2026, raising questions about its security and arrangements.

Source: https://tennews.in/nhrc-questions-himachal-govt-over-19-women-nursing-students-contracting-tb/

National
NHRC questions Himachal govt over 19 women nursing students 'contracting TB'
On May 7, 2026

New Delhi, May 7 (IANS) Taking a strong view, the NHRC has sought a report from Himachal Pradesh after a media report alleged that 19 women students contracted tuberculosis in the hostel of a Nursing College in Shimla, an official said.

Taking suo motu cognisance of a media report over the alleged incident, the National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Chief Secretary, Himachal Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Reportedly, during two recent inspections of the premises, serious deficiencies were observed in the management of the hostel, including sanitation and overall institutional functioning. However, no corrective measures were taken by the authorities, and as a result, the students contracted tuberculosis.

The Commission observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

The media report, carried on May 2, highlighted several shortcomings based on the two inspections of the institutions held on March 31 and April 17.

The students at the hostel face overcrowded, damp, and unhygienic living conditions with severely inadequate sanitation. Food quality is poor and lacks basic nutrition. They are reportedly denied rest during illness and forced to work as "hospital staff" even on holidays, an NHRC statement said.

In a separate case, the NHRC sought a report within two weeks from the Jharkhand government and the district police chief over the death of a 19-year-old woman inmate of a remand home in the Charki Pahadi area of the Deoghar district earlier this month, an official said.

The NHRC took suo motu cognisance of a media report about the death of a 19-year-old female inmate on May 2, allegedly under suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained.

The NHRC observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

It issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand, and the Superintendent of Police, Deogarh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on May 4, when the inmate's condition suddenly deteriorated, the Remand Home staff rushed her to the Deoghar Sadar Hospital, where she died during treatment.

Reportedly, five inmates of this Remand Home have died since January 1 2026, raising questions about its security and arrangements, said a statement.

–IANS

Source: https://risingkashmir.com/kashmiri-pandit-heritage-tour-vision-in-action

Kashmiri Pandit Heritage Tour: A vision in action
ASHWANI KUMAR CHRUNGOO 07 May 2026

The Global Kashmiri Pandit Diaspora (GKPD) has been conscious of this heritage of Kashmir and proposes to organise the first-of-its-kind 'Heritage tour of Kashmir' in the month of June 2026

FRAGRANCE OF IDEAS

Kashmiri Pandits, the indigenous people of Kashmir, have been living in their 37th year of exile far away from their homeland, Kashmir. They were forced to live in exile due to genocide and ethnic cleansing that were inflicted upon them by the terrorists in the valley during and after 1986. After their mass exodus, they were compelled to live in displacement and dispersal.

The National Human Rights Commission (NHRC) said about them that "acts akin to genocide were committed against them". It also said that "they were not given the relief and due understanding that they deserved". However, the community showed resilience, which was also acknowledged by the NHRC, and fought for their survival and existence with all the might at their command. They have a rich history, and the members of the community, dispersed throughout the world, are conscious of it.

Kashmiri Pandits have been living in the Kashmir valley for more than six thousand years. Their traditional almanac which is functional even to date, describes that they lived in the valley of Kashmir from times immemorial and were/are the fundamental founders of the civilisation and history of Kashmir. Their almanack is known as 'Saptarishi-Samvat' and this year (2026-27) is the Saptarishi-Samvat:5102.

All sorts of ancient, medieval and modern literature, philosophy, tradition, arts, science, technology, economics and politics bear their handprints & footprints which no one on this earth could till date erase or finish from their existence as witness to history. These are the mirror of Kashmir's rich civilisation and history and are sacred and sacrosanct for generations after generations of the Kashmiri Pandit community.

The Global Kashmiri Pandit Diaspora (GKPD) has been conscious of this heritage of Kashmir and proposes to organise the first-of-its-kind 'Heritage tour of Kashmir' in the month of June 2026. The tour was initially going to be organised in September 2024, but due to the elections in Jammu and Kashmir, the tour couldn't be executed in the year 2024. In the year 2025, the Pahalgam terror incident, in which 26 Hindus were killed, compelled the organisers to postpone it by one year. The GKPD has finally decided to make it happen this year in the month of June, from 6th June to 14th June.

The GKPD declared that 'after decades of exile, the time has come for Kashmiri Pandits to embark on a journey of rediscovery—an odyssey back to the land of our ancestors, where the sacred rivers carry the echoes of our mantras, and the mountains stand tall, silent witnesses to our wisdom. This is more than a heritage tour; it is a reclamation of memory, a revival of spirit, and a promise to our youth—that they will walk the hallowed paths of their forebears, stand before the timeless shrines of Sharika, Ragnya, and Martand, experience Bhairava and feel

the pulse of a civilisation that refused to be erased.

The journey in the valley will start on 6th June 2026 from Srinagar and will last for one week up to 12th June 2026. The tour will be immediately followed by a two-day conclave of GKPD at SKICC, Srinagar, on 13 and 14 June 2026. The whole programme has been specially designed for the youth of the displaced Kashmiri Pandit community who have been detached from their homeland, Kashmir, for the last 36 years. Delegates from all over the world are getting themselves registered for the event. The programme will be attended by a large number of dignitaries from various fields of life.

The GKPD has already made contact with the Central government, in addition to the government of Jammu and Kashmir, in connection with the organisation of the event and also in regard to the security and safety of the visiting participants in the valley. The GKPD says, "Participation in the Kashmir Yatra/Pilgrimage is entirely voluntary. The organisers and facilitators shall not be held liable or responsible for any personal injury, illness, loss, damage, accident, delay, or unforeseen event—including but not limited to force majeure—that may occur before, during, or after the event". This is particularly brought to the notice of the government and the administration for its role in the context of the successful organisation of the historical event.

The detailed information and the contents regarding the programmes during the whole event is/will be available on the various portals of GKPD. The information will flow from the following office bearers of the GKPD and its associates: Utpal Kaul, Delhi, Dr. Surinder Kaul-USA, Rakesh Kaul-USA, Kashi Akhoon-Delhi and Ashwani Bhat-Mumbai. The Associates of GKPD regarding the whole event are the following: Kashmir Overseas Association-US, Kashmiri Pandit Association-Mumbai, JK Vichar Manch-Delhi, Sanjeevani Sharda Kendra, Jammu, AIKS Youth-Jammu and AMEAK-Srinagar.

The Sarkaryawah of RSS, Dattatreya Hosebole, who was on a visit to the US recently, had a meeting with Dr. Surinder Kaul at Houston and discussed the Heritage tour project of GKPD with him. After the important meeting, GKPD circulated the following message to its associates, activists and the general public for their information and knowledge:

"As part of an outreach campaign to engage with organisations and stakeholders across the political spectrum in India, Dr. Surinder Kaul, Co-Founder of the Global Kashmiri Pandit Diaspora (GKPD), held a one-on-one meeting with Dattatreya Hosabale, Hon’ble General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, in Houston on April 20, 2026.

During the 90-minute, in-depth and candid interaction, Dr. Kaul sought support and guidance from Hosabale Ji for the upcoming Global Kashmiri Pandit Heritage Tour and the two-day Global KP Conclave scheduled to be held in Srinagar from June 6 to June 14, 2026.

Dr. Kaul also highlighted a range of critical issues, including the ongoing relief measures, as well as the persistent challenges faced by camp-dwelling Kashmiri Pandits and employees under the Prime Minister’s Package in the Valley.

Hosabale Ji listened attentively to the concerns raised and shared valuable insights and suggestions for the way forward".

This is indeed a very important development so far as the successful organisation of the whole event is concerned. The chief organisers and their associates for this event have expressed their satisfaction with the above-mentioned meeting. It is expected that the project will receive the desired support from different shades of opinion within the society, and efforts are afoot to have the participation of displaced Kashmiri Sikhs also in the event.

The Heritage tour will begin on 6th June 2026 from the summer capital of the Union Territory of Jammu and Kashmir - the Srinagar city. It will thereafter visit the following important venues, which have great importance in the civilisation and history of Kashmir from the point of view of the Kashmiri Pandits:

Source of Mata Vitasta at Vetha-Vatur & Omah Mandir, Sidha Lakshami Peeth, Lok Bhawan, Mata Shiva Bhagwati-Akingam, Mata Uma Devi-Brari Angan, Mata Tripura Sundari, RKMS Vivekananda Kendra-Nagdandi, Logripura & Martand Surya Mandir, Pahalgam-Chandanwari & Mamleshwar Mandir, Bhairav caves, Vasuki Naag-Hushur & Baidpore, Raithan Teerth, Shankeracharya Mandir, Mata Zeishta Devi Mandir, Mata Sharika Devi Mandir-Hari Parbat & Chatti-Patshahi, Swami Laxman joo Ashram, Ram Chandra Mandir, Raghunath Mandir & Ganpatyar, Swami Gopinath ji Ashram, Mata Kheer Bhawani-Tullamulla, Mata Roop Bhawani Mandir-Waskura, Nandkeshwar Mandir-Sumbal, Sharda Mata Mandir-Gushi, Bhadrakali Mandir-Handwara, Mata Sharda Mandir-Teetwal & Gugloosa, Mata Shailputri Mandir, Koti Teerth & Venkura Mandir-Baramulla.

The above given itinerary covering most of the Kashmir valley will be followed by a two-day conclave on the banks of Dal Lake in the SKICC hall in Srinagar on 13-14 June 2026. It is expected that the conclave will be attended by the delegates of the Heritage tour, activists of GKPD and its associates to the event, important and prominent dignitaries and representatives of the government and administration. Since the whole event has no political agenda and is mainly focussed on the heritage of Kashmir and its connection with the youth of the displaced community, various organisations will be eager to participate in the conclave. However, the admission will be restricted to the delegates and the pass-holders only.

The GKPD calls the heritage tour a pilgrimage, and in this context, their view, as per its brochure, is summed up here:

"Kashmir, the land of snow-clad mountains, lush valleys, and ancient temples, has long been a sacred abode for devotees seeking spiritual solace. This 6-day pilgrimage itinerary has been thoughtfully designed to take yatris through the holy teerth-sthans, shakhti-peethas, historic mandirs, and spiritual ashrams of South, Central and North Kashmir. The journey begins with the revered shrines of Mata Vitasta and Martand Surya Mandir in Anantnag, ascends through the scenic valleys of Pahalgam, and continues to the spiritually significant sites of Srinagar, Gulmarg, Varmul (Baramulla) and Kupwara. It culminates at the border tirtha of Sharda peeth in Teetwal, a site of immense historical and religious importance.

This pilgrimage is not merely a journey across landscapes but a journey of the soul connecting the devotee with centuries of devotion, divine energy, and the spiritual heritage of Kashmir. Along the way, participants will have the opportunity to engage with the local Kashmiri Pandit community, witness traditional rituals, and partake in shared experiences that foster devotion, learning and unity.

May this yatra inspire inner peace, reinforce faith, and leave all participants enriched by the eternal blessings of the divine presiding deities of the valley.

In the concluding part, there is no further to add than the prayer for the success of the whole event. Here, it becomes important to appeal to the administration of Jammu and Kashmir and particularly the Divisional Commissioner of Kashmir and the Deputy Commissioner of Srinagar district, to extend their cooperation to the organisers for the smooth and successful conduct of the programme.

Source: https://uditvani.in/new-delhi/nhrc-notice-jharkhand-government-deoghar-remand-home-inmate-death/

झारखंड के रिमांड होम में मौत: NHRC ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी
Udit Vani—May 7, 2026

उदित वाणी, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार और जिला पुलिस प्रमुख से देवघर जिले के चरखी पहाड़ी इलाके में स्थित एक रिमांड होम में 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत के मामले में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है.
एनएचआरसी ने 2 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में कथित तौर पर 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया. उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. एनएचआरसी ने पाया कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है.
इसने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
4 मई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई, तो रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.
एक बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर 1 जनवरी 2026 से इस रिमांड होम के पांच कैदियों की मौत हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठते हैं.
एक अलग मामले में, आयोग ने 2 मई को हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी में सीवर की सफाई करते समय दो सफाईकर्मियों की मौत की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भवन के एस्टेट मैनेजर के निर्देश पर श्रमिकों ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण या गैस मास्क के मैनहोल में प्रवेश किया था.
आयोग ने पाया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है.
इसलिए, आयोग ने नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, हरियाणा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल होना चाहिए.
नोटिस जारी करते हुए आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एनएचआरसी की सलाह के बावजूद देश में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं.

Source: https://www.aninews.in/news/national/general-news/ncert-races-to-bridge-textbook-gap-only-half-of-planned-books-printed-so-far-for-new-academic-session20260507104458/

NCERT races to bridge textbook gap; only half of planned books printed so far for new academic session
By Vishu Adhana |
Updated: May 07, 2026 10:44 IST

New Delhi [India], May 7 (ANI): Even as the academic session began over a month ago, NCERT is running against time to bridge the demand-supply gap for its textbooks, with only just over half of the planned books printed so far.
NCERT, which has rolled out revised textbooks for Classes 3 to 9 under the new curriculum framework, had planned to print nearly 15 crore books for the 2026-27 academic session. However, only around 7 to 8 crore copies have been printed till now, officials confirmed.
Responding to the query about the demand and supply gap, a senior official in the Ministry of Education said, "We hope in the month of May we will be able to print as many books. NCERT has planned to print about 15 crore books They have printed about 7-8 crore books."
The officials also confirmed that NCERT will be able to meet the supply gap by the end.
The delay has left many students without access to the new textbooks, even though the academic session commenced on April 1.
On being asked how students are coping with the absence of revised books, the officials said, "There are previous years' books and students are studying them."
Apart from delays in availability, concerns are also mounting over the increasing dependence of private schools on costlier books published by private publishers, placing an additional financial burden on parents. There are allegations that private schools are pushing for private publishers books.
National Human Rights Commission member Priyank Kanoongo also alleged that an "education mafia" was attempting to derail a government push for affordable schoolbooks.
In a post on X, Kanoongo said he had directed state governments to ensure the use of affordable NCERT and SCERT books in place of expensive private publisher books in private schools. He said the move has been taken under the powers of the Protection of Human Rights Act, 1993, within the framework of the Right to Education (RTE) Act, 2009.
Responding to these complaints, the senior official said CBSE has urged the private schools to use NCERT books. (ANI)

News Mill, Online News, 08/05/2026

Source: https://thenewsmill.com/2026/05/ncert-prints-just-half-of-textbooks-planned-for-2026-27-academic-session/

Nation and Beyond
NCERT prints just half of textbooks planned for 2026-27 academic session
Photo of author
TNM (With ANI Inputs)
Published On: May 7, 2026

New Delhi, May 7 – The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is striving to address the shortage of textbooks, with only just over half of the intended print run completed for the 2026-27 academic session, which began more than a month ago.
NCERT had planned to print nearly 150 million textbooks covering revised curricula for Classes 3 to 9. However, officials confirmed that approximately 70 to 80 million copies have been printed to date.

When asked about the gap between demand and supply, a senior Ministry of Education official stated, "We hope in the month of May we will be able to print as many books. NCERT has planned to print about 15 crore books. They have printed about 7-8 crore books." The official also assured that the remaining supply would be completed by the end of the month.

The delay has resulted in many students lacking access to the updated textbooks despite the session starting on April 1. Regarding how students are managing without the revised books, officials noted, "There are previous years' books and students are studying them."

Alongside concerns over textbook delays, there is increasing criticism of private schools relying on more expensive books published by private publishers, which places a financial burden on parents. Allegations have arisen that private schools are promoting the adoption of these private publisher textbooks.

Priyank Kanoongo, a member of the National Human Rights Commission, accused an "education mafia" of attempting to obstruct government efforts to promote affordable school textbooks. In a post on X, Kanoongo indicated he had instructed state governments to enforce the use of affordable NCERT and State Council of Educational Research and Training (SCERT) books in private schools instead of costly private publisher books. He added that this directive is issued under the powers granted by the Protection of Human Rights Act, 1993, within the Right to Education Act, 2009 framework.

In response to these issues, the senior official said that the Central Board of Secondary Education (CBSE) has appealed to private schools to adopt NCERT textbooks.

Source: https://www.livehindustan.com/ncr/faridabad/story-national-human-rights-commission-takes-notice-on-deaths-of-two-safai-karamcharis-in-faridabad-201778167638212.html

सफाई कर्मियों की मौत के मामले में प्रशासन को नोटिस
May 07, 2006 08:57
Newswrap हिन्दुस्तान, नीदाबाद

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी

फरीदाबाद, केमाव भारद्वाज। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी के पास सीवर की सफाई के दौरान मारे गए दो सफाई कर्मियों को मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त और नगरनिगम आयुक्त को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

मामले की लापरवाही
आयोग ने दोनों अधिकारियों से इसमामले में हुई लापरवाही की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस मामले में हुई कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन करार दिया है। आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और आयोग की एडवाइजरी के बावजूद सीवर की सफाई सफाई कर्मियो से करवाई जा रही है। जबकि सीवर की सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल करने और सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के नियम-कायदे पहले से ही तय है।

मृतकों की पहचान
बता दे कि दो मई को ग्रेटर फरीदाबाद की पूरी प्रथम सोसाइटी के पास सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में घुसे दो सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान खेड़ी कला गांव निवासी सुपरवाइजर सुनील और राजेंद्र के रूप में हुई थी। जांच में दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क के सीवर में उतारने का आरोप है। इस मामले में बीपीटीपी थाना पुलिस ने मृतकों में से एक सुनीत के भाई लाता की शिकायत पर बीपीटीपी केसंपदा प्रबंधक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था।

Hindustan Times, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/bombay-hc-upholds-acquittal-of-22-persons-sohrabuddin-shaikh-fake-encounter-case-101778135770437-amp.html

Bombay HC upholds acquittal of 22 in Sohrabuddin Shaikh fake encounter case
According to the CBI, Shaikh was killed on November 26, 2005, allegedly by a joint team comprising Gujarat and Rajasthan police
Updated on: May 07, 2026 02:54 pm IST
By HT Correspondent

The Bombay High Court on Thursday dismissed an appeal filed by Rubabuddin Shaikh, challenging a Mumbai sessions court order acquitting 22 people, including several police personnel from Gujarat and Rajasthan, accused of kidnapping and killing his brother Sohrabuddin Shaikh and wife in an alleged staged encounter.
The division bench of chief justice Shree Chandrashekhar and justice Gautam Ankhad dismissed the appeals, saying no case was made out for interfering with the trial court verdict.

The case dates back to November 23, 2005, Sohrabuddin Shaikh, a wanted criminal, his wife Kausar Bi and his associate Tulsiram Prajapati, were allegedly abducted by accused policemen from a bus while they were traveling to Sangli in Maharashtra from Hyderabad. Their bus was intercepted by officers of the Gujarat and Rajasthan police at Zahirabad in Telangana and the trio was nabbed. Shaikh and Kausar Bi were taken to Gujarat while Prajapati, who was held in custody, was arrested from Bhilwara in Rajasthan on November 26, 2005.

According to the Central Bureau of Investigation (CBI), the police officers killed Sohrabuddin in a fake encounter on the intervening night of November 25, 2005 and November 26, 2005. Kausar Bi too was killed after that and her body was burnt on November 28, 2005. A year later, Prajapati who was lodged in an Udaipur jail was brought to Ahmedabad by the police in another case of firing and produced before a magistrate.
The CBI had said that Prajapati had expressed his fear of being eliminated in a police encounter to his jail inmates, lawyer and the National Human Rights Commission (NHRC). On their journey back to Udaipur with Prajapati, the police had claimed he tried to flee with the help of two others who threw chilli powder at the police guards escorting Prajapati. At about 5am on December 28, 2006 Prajapati too was killed in an encounter which the CBI claimed was a farce. The CBI had alleged that the accused policemen wanted to kill Prajapati because he was a witness to the abduction of Sohrabuddin and Kausar Bi.
Twenty-two accused including policemen from Gujarat, Rajasthan and Hyderabad stood trial in the case for charges including murder, criminal conspiracy and others. They were acquitted by a special CBI court in Mumbai in 2018. According to the CBI that took over the investigation in the case in 2010 following directions of the Supreme Court, the accused policemen claimed that Shaikh was a member of
Lashkar-e-Toiba, a terror organisation, was killed in an encounter on November 26, 2005, when he was in Gujarat to murder a 'big political leader'.
Shaikh's brother, Rubabuddin, had written a letter to the Chief Justice of India in 2006, seeking an inquiry into the encounter that, he claimed, was fake. In 2006, based on the top court's directions, when a preliminary inquiry was carried out in the case, the then Gujarat policeman VL Solanki sought to examine Prajapati, claiming that he was a witness to Shaikh's abduction. The CBI had said that Solanki had requested permission to examine Prajapati on December 18, 2006, but just ten days later, Prajapati was killed in a fake encounter on December 28, 2006, also in Gujarat. Prajapati's mother, Narmadabai, also filed a petition before the Supreme Court, seeking an inquiry.

The trial in the case concluded on December 21, 2018 with the acquittal of all the accused. Of the 210 witnesses examined during the trial, 92 had turned hostile.

Source: https://www.univarta.com/news/india/story/3835819.html

एनएचआरसी ने नर्सिंग कॉलेज हॉ स्टल में छा त्राओं के तपेदिक से ग्रसित हो ने
का स्वतः संज्ञा न लिया

नयी दि ल्ली 07 मई (वा र्ता) रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग (एनएचआरसी) ने हि मा चल प्रदेश में शि मला स्थि त एमजी एमएससी नर्सिं ग कॉ लेज हॉ स्टल में 19 छा त्रा ओं के तपेदि क से ग्रसि त हो ने की मी डि या रि पो र्ट पर स्वतः संज्ञा न लि या है।
एनएचआरसी ने गुरुवा र को बता या कि आयो ग ने हि मा चल प्रदेश के शि मला स्थि त एमजी एमएससी नर्सिं ग कॉ लेज हॉ स्टल में 19

Dainik Bhaskar, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-jharkhand-remand-home-death-nhrc-seeks-govt-police-report-within-two-weeks-20260507195103-1293303

झारखंड के रिमांड होम में मौत एनएचआरसी ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी
7 May 2026 11:31 PM

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार और जिला पुलिस प्रमुख से देवघर जिले के चरखी पहाड़ी इलाके में स्थित एक रिमांड होम में 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत के मामले में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार और जिला पुलिस प्रमुख से देवघर जिले के चरखी पहाड़ी इलाके में स्थित एक रिमांड होम में 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत के मामले में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने 2 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में कथित तौर पर 19 वर्षीय महिला कैदी की मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। एनएचआरसी ने पाया कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। इसने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 4 मई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई, तो रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर 1 जनवरी 2026 से इस रिमांड होम के पांच कैदियों की मौत हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। एक अलग मामले में, आयोग ने 2 मई को हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी में सीवर की सफाई करते समय दो सफाईकर्मियों की मौत की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भवन के एस्टेट मैनेजर के निर्देश पर श्रमिकों ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण या गैस मास्क के मैनहोल में प्रवेश किया था। आयोग ने पाया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, हरियाणा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल होना चाहिए। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एनएचआरसी की सलाह के बावजूद देश में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Tribune, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.dainiktribuneonline.com/news/gurugram/human-rights-commission-issues-notice-to-faridabad-municipal-corporation-police-commissioner/

फरीदाबाद नगर निगम, पुलिस आयुक्त को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
Our Correspondent
फरीदाबाद, Updated At : 11:19 PM May 07, 2026 IST

फरीदाबाद नगर निगम, पुलिस आयुक्त को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
article_Author
Our Correspondent
फरीदाबाद, Updated At : 11:19 PM May 07, 2026 IST
fb
twitter
whatsapp
featured-imgfeatured-img
मैनहोल। सांकेतिक फोटो
Advertisement
ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी के सामने सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की पूरी जानकारी शामिल की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की घटनाएं सफाई कर्मियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं।

दरअसल, बीते 2 मई को ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्राणायाम सोसाइटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान गांव खेड़ी निवासी सुनील और राजेंद्र के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क के सीवर में उतारा गया था। सीवर के अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण दोनों की हालत बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों कर्मचारी बीपीटीपी से जुड़े हुए थे और एस्टेट मैनेजर के कहने पर उन्हें मैनहोल में सफाई के लिए उतारा गया था। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था।

मानवाधिकार आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह मामला मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रतीत होता है। आयोग ने यह भी चिंता जताई कि भारत का सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा.निर्देशों और आयोग की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।

आयोग ने कहा कि सीवर सफाई के लिए मशीनों के उपयोग और सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद कई स्थानों पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे सफाई कर्मियों की जान जोखिम में पड़ रही है।

क्या कहते है पुलिस पीआरओ

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Jagran, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-jharkhand-high-court-reserves-verdict-on-custody-deaths-pil-40230874.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

पुलिस कस्टडी में 500 मौतें पर सुनवाई पूरी: हाई कोर्ट तय करेगा क्या झारखंड सरकार ने मानवाधिकार नियमों का किया पालन?
By Manoj Singh
Edited By: Chandan Sharma
Updated: Thu, 07 May 2026 04:14 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत और जेल में हुई मौतों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने गृह सचिव से न्यायि ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में पुलिस हिरासत और जेल में हुई मौत की घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जारी दिशा-निर्देश के अलावा बीएनएसएस का 196 सब सेक्शन (2) को अदालत में दाखिल किया गया है।

मामले में पूर्व में गृह सचिव ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस और जेल कस्टडी में वर्ष 2018 से 2025 के बीच करीब 500 लोगों की मौत हुई है, इनमें से करीब आधे की न्यायिक जांच नहीं हुई है।
अदालत ने गृह सचिव से स्पष्ट रूप से यह पूछा था कि राज्य में हुई हिरासत में मौत की घटनाओं में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि शपथ पत्र में बताया जाए कि न्यायिक जांच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया या नहीं।

सरकार की ओर से पूर्व की सुनवाई में अदालत को यह बताया गया था कि हिरासत में मौत के सभी मामलों की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई थी। जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि मजिस्ट्रेट द्वारा जेल या न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में कोई जांच की गई थी या नहीं।

बता दें कि प्रार्थी मुमताज अंसारी ने अदालत से राज्य में जेल या न्यायिक हिरासत में हुई मौत मामलों की जांच करने का आदेश देने का आग्रह किया है।

Amar Ujala, Online News, 08/05/2026

Source: https://www.amarujala.com/delhi-ncr/faridabad/notice-issued-to-municipal-corporation-and-police-commissioner-in-the-case-of-death-of-sanitation-workers-faridabad-news-c-26-1-fbd1021-69385-2026-05-08

Faridabad News: सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी
Noida Bureauनोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 12:04 AM IST

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दो सप्ताह के अंदर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी के सामने रविवार को सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से मामले को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति और मृतकों के परिजन को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी शामिल करने को कहा है।

रविवार दो मई को पुरी प्राणायाम सोसाइटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान गांव खेड़ी निवासी सुनील और राजेंद्र की दम घुटने से मौत हो गई थी। दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतारा गया था। आरोप है कि दोनों बीपीटीपी के कर्मचारी थे और एस्टेट मैनेजर के कहने पर सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एनएचआरसी की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सीवर सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल और सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।

सफाई कर्मचारियों की मौत पर नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दो सप्ताह के अंदर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

बल्लभगढ़। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पुरी प्राणायाम सोसाइटी के सामने रविवार को सीवर की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से मामले को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति और मृतकों के परिजन को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी शामिल करने को कहा है।

रविवार दो मई को पुरी प्राणायाम सोसाइटी के बाहर सीवर की सफाई के दौरान गांव खेड़ी निवासी सुनील और राजेंद्र की दम घुटने से मौत हो गई थी। दोनों कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतारा गया था। आरोप है कि दोनों बीपीटीपी के कर्मचारी थे और एस्टेट मैनेजर के कहने पर सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एनएचआरसी की एडवाइजरी के बावजूद देश में अब भी सीवर की मैनुअल सफाई के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सीवर सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल और सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।

मानवाधिकार संगठन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लोगों को करेंगे जागरूक

चंडीगढ़। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-करप्शन फोर्स चंडीगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक सेक्टर-35 स्थित होटल पार्क इन में आयोजित की गई। अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंछी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 'बैगर मुक्त चंडीगढ़' अभियान और मानवाधिकार संरक्षण को लेकर आगामी रणनीति साझा की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बीरेन दवे मुख्य अतिथि और डॉ. जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक के बाद संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। चेयरमैन अनिल वोहरा और अध्यक्ष पंछी ने राज्यपाल को 'बैगर मुक्त चंडीगढ़' अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत शहर के स्कूलों, ट्रैफिक पॉइंट्स और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 30,000 पंपलेट वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल ने इस सामाजिक पहल की सराहना की। बैठक में चेयरमैन अनिल वोहरा और कमलजीत सिंह पंछी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Shimla, 08/05/2026

Page No: 3, Size: 40.08cm × 14.00cm

एनएचआरसी ने प्रशिक्षुओं के टीबी संक्रमित होने की मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, शिमला : रामपुर के खनेरी स्थित महात्मा गांधी मेडिकल सर्विसेज एंड नर्सिंग संस्थान की 17 प्रशिक्षु नर्सों के टीबी संक्रमित मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश के मुख्य सचिव से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यदि सामने आए आरोप सही हैं तो यह प्रशिक्षु नर्सों के मानवाधिकारों के उल्लंघन है। आयोग ने हास्टल की बदहाल व्यवस्था, गंदगी, भीड़भाड़ औरलापरवाही पर चिंता जताई है।

31 मार्च और 17 अप्रैल को संस्थान व हास्टल का निरीक्षण किया गया था। दूसरी बार एसडीएम स्तर पर हुई जांच में हास्टल की हालत बेहद खराब पाई गई थी। रिपोर्ट में सामने आया कि छात्राएं सीलन भरे कमरों में रहने को मजबूर थीं, सफाई की व्यवस्था नाममात्र की थी और भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी। कमियां उजागर होने के बावजूद सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। हालात लगातार बिगड़ते रहे और आखिरकार 17 छात्राएं टीबी संक्रमित पाई गई। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने दावा किया कि केवल दो छात्रा टीबी से पीड़ित हैं, बाकी छात्राओं को दवाएं दी जा रही है ताकि वह भी टीबी से संक्रमित न हो।

रिपोर्ट में दावा किया है कि बीमार छात्राओं को आराम तक नहीं दिया गया। छुट्टियों के दौरान भी उन्हें अस्पताल स्टाफ की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। इससे छात्राओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा।